नईदुनिया

13 फीसदी कमाई बढ़ने के बाद भी 12 हजार कर्मियों को गूगल ने निकाला, 17, 500 करोड़ रुपए चुकाए

नई दिल्ली।

गूगल ने 2023 में अपने 12 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। उन्हें बर्खास्तगी के लिए 210 करोड़ डॉलर यानी करीब 17,500 करोड़ रुपये भी चुकाए। साल 2024 के पहले महीने में भी एक हजार से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, इसके लिए करीब 70 करोड़ डॉलर खर्च किए।

गूगल की मालिकाना कंपनी अल्फाबेट ने साल की चौथी तिमाही में हुई कमाई का लेखा-जोखा जारी किया, जिसमें इसका खुलासा हुआ है। खास बात है कि इस चौथी तिमाही में अमेरिकी टेक कंपनी और सबसे बड़े इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने 8,600 करोड़ डॉलर यानी 7.14 लाख करोड़ रुपये कमाए। यह पिछले साल से 13 फीसदी अधिक हैं। इसके बावजूद वह लगातार कर्मचारियों को निकाल रही है। साथ ही, अपने कृत्रिम मेधा कार्यक्रम जैमिनी युग में निवेश बढ़ा रही है और ज्यादा कर्मचारियों को भी लगा रही है। इसकी वजह से कंपनी कुछ अन्य सेवाओं को इस साल बंद कर सकती है, जिससे और भी कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। 2023 में अपने कुछ ऑफिस भी गूगल ने बंद किए। इन पर उसे 180 करोड़ डॉलर खर्च करने पड़े।

प्रमुख स्रोतः कहां से कितना कमा रहा गूगल

गूगल क्लाउड: 919 करोड़ डॉलर कमाए, 25.6 प्रतिशत इजाफा। हालांकि, अब भी इस क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट के अजूर व अमेजन वेब सर्विसेस के बाद तीसरा। सर्च इंजन: 4,800 करोड़ डॉलर कमाए। यहां भी 13 फीसदी इजाफा हुआ। सदस्यता शुल्क: 1,070 करोड़ डॉलर। इसमें यूट्यूब प्रीमियम व म्यूजिक, यूट्यूब टीवी, गूगल वन शामिल। पिछले साल से 15 प्रतिशत वृद्धि।

गूगल का 'जैमिनी युग'

अल्फाबेट साल 2024 को जैमिनी युग बता रही है। खुद गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने निवेशकों से बातचीत में बताया, यह एक एआई तकनीक आधारित लैंग्वेज मॉडल है। इसके जरिये साहित्य से लेकर कोडिंग तक, कई प्रकार की सामग्री बनाई जा सकती है। इसे गूगल के बड़े डाटा का लाभ मिल रहा है, जिससे यह बाकी एआई मॉडल से बहुत शक्तिशाली माना जा रहा है। इसका आधुनिक प्रारूप जैमिनी अल्ट्रा जल्द जारी हो सकता है।

न्यूज ब्रीफ

मंत्रिमंडल ने भारत-यूएई द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी, होगा ये फायदा

नई दिल्ली। सरकार ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। एक आधिकारिक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई। बयान में कहा गया, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और यूएई के बीच बीआईटी पर हस्ताक्षर और अनुमोदन को मंजूरी दी है। बयान में कहा गया कि इस संधि से निवेशकों, विशेषकर बड़े निवेशकों का भरोसा बढ़ने की उम्मीद है। इसके चलते विदेशी निवेश और विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) के अवसरों में वृद्धि होगी। आगे चलकर रोजगार सृजन पर इसका सकारात्मक असर हो सकता है। बयान के मुताबिक, ''इस मंजूरी से भारत में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। इससे घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने, आयात पर निर्भरता कम करने, निर्यात बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।'' दोनों देशों ने मई, 2022 में एक मुक्त व्यापार समझौता भी लागू किया था। भारत में अप्रैल, 2000 से सितंबर, 2023 के बीच 16.7 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है।

अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के दौरान जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 11.6 प्रतिशत बढ़ा, हुआ इतना कलेक्शन

नई दिल्ली। अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 की अवधि के दौरान, संचयी सकल जीएसटी संग्रह में सालाना आधार पर 11.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह अप्रैल से जनवरी के दौरान यह 16.69 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। पिछले वर्ष की इसी अवधि, अप्रैल 2022-जनवरी 2023 के बीच जीएसटी के रूप में 14.96 लाख करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने इससे जुड़े आंकड़े जारी किए। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2024 में एकत्र किया गया सकल जीएसटी राजस्व रु. 1,72,129 करोड़ है, जो जनवरी 2023 में एकत्र किए गए रु. 155,922 करोड़ के राजस्व से सालाना आधार पर 10.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह अब तक का दूसरा सबसे अधिक मासिक जीएसटी संग्रह है और इस वित्तीय वर्ष में तीसरे महीने 1.70 लाख करोड़ रुपये या उससे अधिक का जीएसटी संग्रह किया गया है। उक्त अवधि के दौरान सरकार ने आईजीएसटी संग्रह में सीजीएसटी के रूप में 43,552 करोड़ रुपये और एसजीएसटी मद में 37,257 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया गया। अप्रैल 2023 में अब तक का सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन किया गया था। उस दौरान जीएसटी के रूप में 1.87 लाख करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे।

पेटीएम के शेयरों में 20 प्रतिशत की गिरावट, आरबीआई के आदेश के बाद दिखा असर

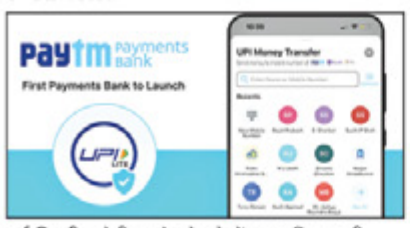

नई दिल्ली। पेटीएम के शेयरों में 20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट में जमा या टॉप अप स्वीकार करना बंद करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद पेटीएम के शेयरों के गिरावट दर्ज की गई है। बीएसई पर स्टॉक 20 प्रतिशत गिरकर 608.80 रुपये पहुंच गया। वहीं एनएसई में 19.99 प्रतिशत गिरकर 609 रुपये की दिन की न्यूनतम ट्रेडिंग सीमा पर पहुंच गया। बता दें शुरूआती कारोबार में कंपनी का बाजार पूंजीकरण (एमकैप) भी 9,646.31 करोड़ रुपये घटकर 38,663.69 करोड़ रुपये रह गया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि यह निर्देश लगातार गैर अनुपालन चिंताओं के बाद दिया गया है। आरबीआई ने यह भी कहा कि पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के नोडल खाते को जल्द से जल्द किसी भी स्थिति में 29 फरवरी, 2024 से पहले खत्म किया जाना चाहिए। ओसीएल के पास 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। गौरतलब है कि आरबीआई के आदेश से कंपनी के सालाना ऑपरेशनल प्रॉफिट पर 300-500 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा।

पिछले नौ वर्षों में तेजी से बढ़ी अर्थव्यवस्था, मोदी सरकार के दूरदर्शी फैसलों का दिखा असर

नई दिल्ली।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत के आर्थिक विकास को सराहा है। आईएमएफ का कहना है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाले देश के रूप में उभरा है। डिजिटलीकरण और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों के कारण भारत वैश्विक विकास में 16 प्रतिशत से अधिक योगदान कर सकता है।

आर्थिक मोर्चे पर प्रमुख उपलब्धियां

भारत की वास्तविक जीडीपी ने वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल-सितंबर 2023) में 7.7 फीसदी की वृद्धि दर्ज की, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। पहली तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी 7.8 फीसदी बढ़ी और दूसरी तिमाही में 7.6 फीसदी बढ़ी। वर्ष 2023-24 में, साल-दर-साल के आधार पर जीडीपी 7.2 फीसदी की दर से बढ़ी। भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.3 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। आईएमएफ ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अपना विकास अनुमान बढ़ाकर 6.7 फीसदी कर दिया है, जो पहले 6.3 फीसदी था।

भारत का आर्थिक परिदृश्य काफी बेहतर

वहीं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के आर्थिक आउटलुक में 2024 के लिए ज्यादा विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि 0.7-1.7 फीसदी की सीमा में और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए लगभग चार फीसदी होने का अनुमान है। हालांकि, कई संकेतकों से पता चलता है कि भारत का आर्थिक परिदृश्य काफी बेहतर है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती और लचीलापन बना हुआ है। भारतीय शेयर बाजार पहली बार वैश्विक स्तर पर चौथे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है।

मानव विकास में उल्लेखनीय प्रगति

भारत के आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों की मजबूती के साथ-साथ मानव विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नीति आयोग के अनुसार, पिछले नौ वर्षों में लगभग 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आ गए हैं और गरीबी दर में भारी गिरावट आई है, जो 2013-14 में 29.17 फीसदी से घटकर 2022-23 में 11.28 फीसदी रह गई है।

रुपया नौ पैसे बढ़कर 82.95 प्रति डॉलर पर

मुंबई। अंतरिम बजट से पहले शुरुआती कारोबार में रुपया नौ पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82.95 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि रुपया एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। विदेशी बाजार में अमेरिकी मुद्रा की मजबूती और घरेलू बाजारों में नरम रुख के बीच निवेशक सतर्क हैं। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 83.02 प्रति डॉलर पर खुला और फिर 82.95 प्रति डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से नौ पैसे की बढ़त है। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.04 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.24 प्रतिशत की बढ़त के साथ 103.52 पर रहा।

2023 में पहली बार प्लेन में बैठे 3 करोड़ लोग

हर साल यात्रियों की संख्या में 37 प्रतिशत इजाफा, लोगों की आय बढ़ना बड़ी वजह

नई दिल्ली।

भारत में हवाई सफर अब सपना नहीं रहा और धीरे-धीरे लोगों की पहुंच में आ रहा है। साल 2023 में 3 करोड़ भारतीयों ने पहली बार हवाई यात्रा की। इंडिगो के आंकड़ों के हिसाब से देश में हर साल पहली बार हवाई यात्रा करने वाले लोगों की तादाद 37 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। एयरलाइंस कंपनी आकासा की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल कंपनी के यात्रियों में 10 प्रतिशत पहली बार हवाई सफर करने वाले यात्री थे। कैपा इंडिया के सीईओ कपिल कौल कहते हैं- हमारा अनुमान है कि 2024 में विमान से सफर करने वाले लोगों में 15 प्रतिशत यात्री पहली बार सफर करने वाले होंगे।

2024 में 2.5 करोड़ पहली बार यात्रा करेंगे

इस साल करीब 15.5 करोड़ लोग हवाई सफर करेंगे। इनमें से 2.5 करोड़ पहली बार यात्रा करेंगे। कैपा इंडिया की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि उन्होंने पहली बार हवाई यात्रा कर रहे यात्रियों का डेटा कैसे निकाला, लेकिन यह बताया कि हवाई यात्रियों की औसत उम्र 10 साल कम हुई है।

लोगों की आय बढ़ने, छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनने से यात्राएं बढ़ीं

विशेषज्ञ हवाई सफर बढ़ने के पीछे तीन बड़ी वजह बता रहे हैं- पहली लोगों की पारिवारिक आय का बढ़ना, दूसरी तेजी से नए रूट और नए एयरपोर्ट तैयार होना और तीसरी मिडिल क्लास लोगों में वीकेंड वेकेशन मनाने का ट्रेंड बढ़ा है। खास बात यह रही कि छोटे शहरों से यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है।

ग्रेनो प्राधिकरण ने की 44 औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की योजना की शुरुआत, 10 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर

ग्रेटर नोएडा।

प्राधिकरण ने 44 औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की योजना की शुरुआत की, जिससे प्राधिकरण को प्लॉट के एवज में रिजर्व प्राइस से करीब 5 हजार करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि इन औद्योगिक भूखंडों का आवंटन साक्षात्कार के जरिए हो रहा है। इसके अलावा इस योजना से 10 हजार युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलने का अनुमान है। इस योजना की शुरुआत 30 जनवरी को हुई, जिसके साथ ही इसका ब्रोशर भी ऑनलाइन उपलब्ध हो गया।

योजना के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 19 फरवरी: अधिकारी- मिली जानकारी के मुताबिक, अधिकारी ने बताया कि योजना के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 19 फरवरी है। पंजीकरण शुल्क, ईएमडी (अर्नेस्ट मनी डिपोजिट) और प्रोसेसिंग फीस भी 19 फरवरी तक ही जमा की जा सकती है। उन्होंने बताया कि आवंटन के पश्चात इन भूखंडों पर एक माह में ही कब्जा मिल जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एन.जी. रवि कुमार का कहना है कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक निवेश के केंद्र के रूप में उभरा है। उद्यमियों की मांग व जरूरत को देखते हुए स्कीम लांच कर दी गई है। तय समयसीमा में प्लॉट पर पजेशन दे दिए जाएंगे। इससे निवेश के साथ ही हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।

पेपाल 2,500 कर्मचारियों को निकालेगी बाहर, यूपीएस 12 हजार नौकरियों की करेगी छंटनी

नई दिल्ली।

भुगतान सेवा देने वाली पेपाल होल्डिंग्स इस साल लगभग 2,500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है। जबकि यूनाइटेड पार्सल सर्विस इंक (यूपीएस) 12,000 लोगों यानी करीब 2.5 फीसदी की छंटनी कर सकती है। घरेलू आईटी कंपनी विप्रो 100 लोगों को निकालने की योजना शुरू कर दी है। पेपाल के सीईओ एलेक्स क्रिस ने कहा, कारोबार को सही आकार देने के लिए इस साल करीब 9 फीसदी कर्मचारियों को निकाला जा सकता है। हमें तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ने और लाभदायक विकास के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। हम उन क्षेत्रों में निवेश करना जारी रखेंगे जो हमारी वृद्धि में तेजी ला सकते हैं।

टेक कंपनी सेल्सफोर्स ने भी 700 कर्मचारियों (एक फीसदी) को बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला किया है। कंपनी ने 2023 में 10 फीसदी कर्मचारियों को निकाल दिया था। 50,875 कर्मचारी घटे 4 आईटी कंपनियों के दिसंबर तिमाही के अंत तक चार प्रमुख आईटी कंपनियों टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल के कर्मचारियों की संख्या में 50,875 की कमी आई थी।

मार्जिन सुधारने पर विप्रो का जोर - विप्रो मार्जिन में सुधार करने के के लिए मध्य स्तरीय सैकड़ों कर्मचारियों को निकालने की योजना बना रही है। इस महीने की शुरुआत में कर्मियों को सूचना देनी शुरू कर दी गई है। चार प्रमुख आईटी कंपनियों में विप्रो का मार्जिन सबसे कम है। सूत्रों ने

कहा, बदलते बाजार परिवेश के अनुरूप अपने कारोबार और प्रतिभा को बनाए रखना कंपनी की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

मुनाफे पर असर से यूपीएस ने लिया फैसला - यूपीएस के सीईओ कैरोल टोम ने बताया, पिछला साल कठिन और निराशाजनक रहा। सभी कारोबारी सेगमेंट में वॉल्यूम, राजस्व और परिचालन लाभ में गिरावट आई है। अब कंपनी का लक्ष्य लागत में एक अरब डॉलर की कटौती का है। कंपनी के पूरे साल का राजस्व 92 अरब डॉलर से 94.5 अरब डॉलर के बीच रहेगा। कंपनी का तिमाही राजस्व एक साल पहले के 27 अरब डॉलर से गिरकर 24.9 अरब डॉलर रह गया है।

ईबे दवा की गोली बनाने वाले उपकरणों की बिक्री से संबंधित मुकदमे में 5.9 करोड़ डॉलर का भुगतान करने पर सहमत

सैन फ्रांसिस्को।

अमेरिकी न्याय विभाग ने बताया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ईबे उस मुकदमे को निपटाने के लिए 5.9 करोड़ डॉलर का भुगतान करने पर सहमत हो गया है। कंपनी पर आरोप था कि उसने पिल प्रेस मशीनों की बिक्री में सहायता की थी, जिनका इस्तेमाल अवैध दवाओं के निर्माण के लिए किया जा सकता है। विभाग के अनुसार, अपराधियों द्वारा अवैध दवाओं के निर्माण के लिए पिल प्रेस और एनकैप्सुलेटिंग मशीनों का उपयोग किया जा सकता है। पिल प्रेस को नियमित रूप से निर्धारित प्रतिबंधित दवाओं से मिलते-जुलते सांचे, मोहर, या डाई के साथ मिलाकर नकली गोलियां तैयार की जा सकती हैं जो वास्तविक फार्मास्युटिकल दवाओं के समान लगती हैं, जिसमें फेंटेनाइल युक्त गोलियां भी शामिल हैं। नियंत्रित पदार्थ अधिनियम (सीएसए) खरीदारों की पहचान सत्यापन, रिकॉर्ड रखने और ड्रग प्रवर्तन प्रशासन (डीईए) को रिपोर्ट करने की आवश्यकता के द्वारा पिल प्रेस और एनकैप्सुलेटिंग मशीनों सहित कुछ फार्मास्युटिकल विनिर्माण उपकरणों को नियंत्रित करता है। विभाग ने आरोप लगाया कि ईबे ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से बेची गई हजारों

पिल प्रेस और एनकैप्सुलेटिंग मशीनों के लिए इन सीएसए आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया। न्याय विभाग के ओपिओइड महामारी सिविल लिटिगेशन टास्क फोर्स के अध्यक्ष, एसोसिएट अटॉर्नी जनरल वनिता गुप्ता ने एक बयान में कहा, फेंटेनल से युक्त नकली गोलियों का घातक ओवरडोज महामारी में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा, विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपलब्ध प्रवर्तन उपायों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उपकरण बेचने में शामिल कंपनियां जो इन खतरनाक गोलियों को बनाना संभव बनाती हैं, वे नियंत्रित पदार्थ अधिनियम का अनुपालन करें। मौद्रिक निपटान के अलावा, ई-कॉमर्स मंच अपनी निषिद्ध और प्रतिबंधित वस्तुओं की नीति के संबंध में अपने अनुपालन कार्यक्रम को बनाए रखने और बढ़ाने पर सहमत हुआ। डीईए प्रशासक ऐनी मिलग्राम ने कहा, फेंटेनाइल - जिसे पिल प्रेस कर नकली गोलियाँ बनाई जाती हैं, जो असली नुस्खे वाली दवाओं की तरह दिखती हैं - अमेरिकियों को मार रही है। ड्रग तस्कर नकली गोलियां बनाने के लिए पिल प्रेस जैसे उपकरण ऑनलाइन खरीदते हैं। उन्होंने कहा, ईबे और अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को जनता की सुरक्षा के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और जब वे ऐसा नहीं करेंगे, तो डीईए उन्हें जवाबदेह ठहराएगा। इस बीच, ईबे लगभग एक हजार कर्मचारियों या अपने पूर्णकालिक कार्यबल के नौ प्रतिशत को बर्खास्त कर रहा है, और कंपनी आने वाले महीनों में बड़ी संख्या में ठेकेदारों की भी छंटनी करेगी।

उच्च कीमतों से देश में सोने की मांग तीन फीसदी घटकर 747 टन, काउंसिल ने बताई यह वजह

मुंबई। ऊंची कीमतों के कारण 2023 में देश में सोने की मांग तीन फीसदी घटकर 747.5 टन रही है। 2022 में यह 774.1 टन रही थी। विश्व स्वर्णपरिषद (डब्ल्यूजीसी) के मुताबिक, अगर कीमतें ज्यादा अस्थिर नहीं होती हैं तो आगे मांग बढ़कर 800-900 टन तक पहुंच सकती है। वैश्विक मांग पांच फीसदी घटकर 4,448.4 टन रही है। काउंसिल ने कहा, बढ़ती कीमतों से मांग काफी प्रभावित हुई है। अक्तूबर में नवरात्रि के दौरान कीमतों में सुधार से ग्राहकों की मजबूत मांग रही, जिससे नवंबर में दिवाली की बिक्री में बढ़ोतरी हुई। हालांकि, दिसंबर में फिर से मांग 9 फीसदी तक घट गई। 2023 में सोने की कीमत अस्थिर रही। अगर कीमतें ज्यादा अस्थिर नहीं रहीं तो इस साल मांग में तेजी आ सकती है। जूलरी मांग 6 फीसदी गिरी 2023 में जूलरी की मांग छह फीसदी गिरकर 562.3 टन रही है। सोने में कुल निवेश सात फीसदी बढ़कर 185.2 टन रहा है। छड़ और सिक्के में निवेश सात फीसदी बढ़कर 185 टन रहा है। सोने का शुद्ध आयात 20 फीसदी बढ़कर 780.7 टन रहा है।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01,-03, फैक्स नं.- 0755-2553914 e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) रजिस्टर्ड नं.म.प्र./296/भोपाल/2012-2014 आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, डाक पंजीयन क्र. म.प्र./भोपाल/296/2015-2017